

तमिलनाडु शिक्षा विभाग मंत्रालय और सामान्य अधीनस्थ सेवा संगठन

बनाम

तमिलनाडु राज्य और अन्य

23 अक्टूबर, 1979

[वी.आर. कृष्णा अय्यर और आर.एस. पाठक, जे.जे.]

सिविल सेवा - दो सेवाओं का एकीकरण - सरकार की नीति में संशोधन - 'ए' और 'बी' विंग की सेवा, पदोन्नति का अनुपात तय करना, पदोन्नति के लिए अनुपात तय करना और सामान्य वरिष्ठता निर्धारित करने में सेवा की गणना का सिद्धांत- क्या यह अनुज्ञेय और वैध है।

तमिलनाडु राज्य में विभिन्न स्तरों पर प्राथमिक, मध्य और उच्च विद्यालय थे जो सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा चलाए जाते थे जिसमें पंचायतें, जिला बोर्ड और सरकार शामिल थे। धीरे-धीरे, पंचायत स्कूलों को जिला बोर्डों द्वारा अवशोषित कर लिया गया और अंततः बाद वाले द्वारा प्रबंधित स्कूलों को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। 1970 में, राज्य सरकार ने एक प्रमुख नीतिगत निर्णय लिया कि 1 अप्रैल 1970 से सभी जिला बोर्ड स्कूलों को अपने अधिकार में ले लिया जाए। जी.ओ.एम.एस. सं.761 दिनांक 16 मई 1970 द्वारा शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मियों को, तमिलनाडु शैक्षिक अधीनस्थ सेवा नामक शिक्षा विभाग में एक अलग सेवा के रूप में समाहित किया गया था। गैर-शिक्षण कर्मचारियों से संबंधित मंत्रिस्तरीय सेवा को भी

अलग रखा गया था। दो अलग-अलग सेवाओं के रखरखाव का सीधा परिणाम यह हुआ कि जहां सरकारी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति की संभावनाएं उपलब्ध थीं, वहीं वे सरकारी सेवा में शामिल होने पर पूर्व जिला बोर्ड के कर्मचारियों के लिए खुली नहीं थीं। इससे आंदोलन और प्रतिनिधित्व हुआ।

सरकार ने प्रश्न पर नए सिरे से विचार किया और 17 अक्टूबर, 1974 के जी.ओ.1786 द्वारा सेवा को पुनर्गठित किया, ताकि सभी सरकारी स्कूलों के कर्मचारियों को 'ए' विंग कहा जाए और पूर्व जिला बोर्ड स्कूलों के कर्मचारियों को 'बी' विंग के रूप में संदर्भित किया जाए। और निर्णय लिया कि चूंकि विंगों का पूर्ण एकीकरण प्रशासनिक रूप से कठिन था, इसलिए उन्हें तमिलनाडु शैक्षिक अधीनस्थ सेवा और तमिलनाडु शैक्षिक सेवा के दो विंगों के रूप में अलग रखा जाना चाहिए। 'बी' विंग के कर्मियों ने सरकार को बताया कि 1 अप्रैल, 1970 से सरकारी सेवकों के रूप में उनके अवशोषण के बाद से उनके पास पर्याप्त पदोन्नति के अवसर नहीं थे। सरकार ने फिर से मामले की जांच की, इन विंगों को फिर से एकीकृत करने का निर्णय लिया और इस उद्देश्य के लिए 2 नवंबर, 1978 को जी.ओ सं. 1968 पारित किया, जिसमें पदोन्नति के मामले में दोनों विंगों के बीच अनुपात तय करने और सामान्य वरिष्ठता निर्धारित करने में। सेवा की गणना के सिद्धांत का भी प्रावधान किया गया था।

इस न्यायालय में दायर रिट याचिकाओं में, याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि दो अलग-अलग विंगों के एकीकरण के लिए कोई तर्कसंगत फॉर्मूला नहीं था; दोनों विंगों के लिए प्रदान की गई भर्ती के तरीके, योग्यता और वरिष्ठता अलग-अलग होने के कारण, उन्हें एक सामान्य सेवा कैंडर में एकीकृत करना और उनकी सेवा शर्तों को समान करना अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन था। 'बी' विंग के कर्मियों को 1 अप्रैल, 1970 से सरकारी सेवा में शामिल कर लिया गया था, इसलिए सरकारी सेवक के रूप में उनकी पात्रता से पहले की तारीख से वरिष्ठता देने की अनुमति नहीं थी।

हालाँकि, राज्य सरकार ने तर्क दिया कि दोनों विंगों के एकीकरण का निर्णय मामले की विस्तृत जांच करने और दोनों विंगों में विभिन्न श्रेणियों के कर्मियों की संख्या और उनके पदोन्नति के अवसरों को ध्यान में रखने के बाद लिया गया था।

याचिकाओं को खारिज करते हुए-

अभिनिर्धारित किया : 1. जिन छात्रों को परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, ऐसे पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम और शिक्षण की प्रकृति स्कूली छात्रों के दो सेटों में लगभग समान होती है और शिक्षकों की योग्यताएं भी समान होती हैं। इस पृष्ठभूमि में, राज्य ने संभवतः इस तर्क को अस्वीकार्य मान लिया कि सेवा की गुणवत्ता, रोजगार के लिए योग्यता की प्रकृति और अन्य विशेषताएं वास्तव में समान थीं और परिणामस्वरूप जिला बोर्ड स्कूलों में सेवा और सरकारी स्कूलों में वरिष्ठता की गणना के

प्रयोजनों के लिए सेवा को वैध रूप से बराबर किया जा सकता है। समीकरण में गणितीय परिशुद्धता एक व्यर्थ प्रयास है। [1034 बी-सी]

2. सेवा में न्यायशास्त्र एकीकरण एक जटिल प्रशासनिक समस्या है, जहां कई लोगों के साथ व्यापक न्याय करने में, कुछ को चोट लगने से इंकार नहीं किया जा सकता है। संयुक्त भूमिका में कुछ भूमिका, यहाँ तक कि कुछ लड़खड़ाहट, को फॉरेंसिक निगरानी के बिना सरकार पर छोड़ दिया जाना चाहिए, क्योंकि संविधान द्वारा प्रशासन को कार्यपालिका को सौंपा गया है, न्यायालय को नहीं। प्रशासनिक जीवन सहित सभी जीवन में प्रयोग, परीक्षण और त्रुटि शामिल है, लेकिन मौलिक अधिकारों के अग्रणी तार के भीतर, और, असंवैधानिक 'ज्यादतियों' के अभाव में, न्यायिक सुधार सही नहीं है। अनुच्छेद 32 के तहत यह न्यायालय संवैधानिक प्रहरी है, राष्ट्रीय लोकपाल नहीं। [1031 ए-बी]

मौजूदा मामले में, भले ही कोटा नियम एकीकृत प्रक्रिया में न्याय लाने के लिए एक प्रशासनिक उपकरण है, अनुपात मनमाना नहीं हो सकता है और न ही बाहरी कारकों पर आधारित हो सकता है। [1031 - डी]

3. दोनों समकक्ष समूहों की कुल संख्या का यथार्थवादी ध्यान रखते हुए, मंत्रालयिक कर्मचारियों और शिक्षण कर्मचारियों के लिए क्रमशः 5:3 और 3:2 का अनुपात निर्धारित किया गया था। क्वांडोम जिला बोर्ड के सेवक और रिश्तेदार सरकारी स्कूल कर्मचारी। यह कोई अतार्किक मानदंड

नहीं है जब दो स्रोतों से निकलने वाली दो धाराओं का सहसंयोजन होता है।

[1030 एच]

4. जिला बोर्ड में शामिल किए जाने वाले कर्मचारियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, अनुपात तर्कसंगत है। एक बेहतर फार्मूला विकसित किया जा सकता है, लेकिन अदालत सरकार की बुद्धि की जगह अपनी बुद्धि नहीं ले सकती, सिवाय इसके कि यह देखने के लिए कि अनुचित विकृति, दुर्भावनापूर्ण हेरफेर, अक्षम्य मनमानी और इसी तरह की कमजोरियां एकीकरण के समीकरण को अपवित्र नहीं करती हैं। [1031 एफ]

5. राज्य द्वारा सीधे तौर पर अपने अधिकार में ले लिए गए सभी स्कूलों के कर्मियों को बुनियादी ढांचे में बुना जाना था। इस उद्देश्य के लिए कुछ प्रासंगिक सूत्र प्रस्तुत किए जाने थे ताकि समरूपीकरण एक समूह या दूसरे को अनुचित रूप से नुकसान न पहुँचाए। 1970 में सरकार ने एकीकरण का नहीं, बल्कि पृथक रखने का निर्णय लिया। बाद में इस नीति को छोड़ दिया गया। यदि प्रशासनिक नीति को संशोधित किया जाता है तो अदालत न तो झगड़ा कर सकती है और न ही आदेश को रद्द कर सकती है क्योंकि सरकार ने प्रश्नकाल में जवाब दिया है या एक संवेदनशील मंत्री के कहने पर निर्णय की दोबारा जांच की है। [1031 एच-1032 सी]

6. समीकरण के क्षेत्र में. एक समग्र दृष्टिकोण, न कि एक सूक्ष्म विच्छेदन, मायने रखता है। [1033 सी]

7. नीति स्थिर नहीं है, बल्कि गतिशील है और जब पंचायत संस्थाओं को जिला बोर्ड संस्थाओं के साथ मिला दिया गया था, तब सरकार पर जो असर पड़ा था, उसे अनुभव या बदली हुई परिस्थितियों के मद्देनजर छोड़ दिया गया होगा। जिसे प्रशासनिक रूप से अव्यावहारिक माना गया था, बाद में विचार और कार्यकर्ताओं के पुनर्विचार के बाद वह व्यवहार्य और निष्पक्ष साबित हो सकता है। न्यायालय किसी जी.ओ. या नीति को केवल इसलिए रद्द नहीं कर सकती क्योंकि उसमें भिन्नता या विरोधाभास है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि क्या दुर्भावनाएँ दूषित करती हैं या अतार्किक और बाहरी कारक दूषित करते हैं। [1034 जी-एच, 1035 ए]

8. एक बार जब सिद्धांत तर्कसंगत पाया जाता है तो तथ्य यह है कि कठिनाई के कुछ अजीब उदाहरण दोनों तरफ उत्पन्न हो सकते हैं, आदेश या नीति को अमान्य करने का आधार नहीं हो सकता है। कल के वरिष्ठों को आज कनिष्ठ बनते देखना कितना भी दुखद क्यों न हो, यह एक ऐसा क्षेत्र है, जहां मनमानी और अतार्किकता के अभाव में, न्यायालय को एक हाथ बंद करने की नीति अपनानी पड़ती है। [1035 सी-डी]

मूल क्षेत्राधिकार: रिट याचिका संख्या 272 और 399/1979

(संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

एस. वी. गुप्ते (399/79), एस. गोविंद स्वामीनाथन (272/79),
के.आर.चौधरी और एन.एस.सिवम, याचिकाकर्ताओं की ओर से।

के. के. वेणुगोपाल, अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल, ए. वी. रंगम, प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से।

वाई. एस. चिताले, ए. के. सेन, पी. एन. रामलिंगम, आर. मोहन और ए. टी. एम. संपत, प्रतिवादी संख्या 3-4 की ओर से।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया-

कृष्णा आयर, न्यायाधिपति. - संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इन दो रिट याचिकाओं में इस न्यायालय के फैसलों में शामिल अनुच्छेद 14 और 16 पर आधारित समान, हालांकि परिचित, संवैधानिक प्रश्न शामिल हैं। प्रस्तुतियों के साथ साथ अपास्ती भी परिचित है। इन कारणों से, तथ्यों का संक्षिप्त वर्णन, कानून की संक्षिप्त व्याख्या और दोनों के लिए एक सामान्य निर्णय पर्याप्त होगा।

तमिलनाडु राज्य में विभिन्न स्तरों, प्राथमिक, मध्य और उच्च स्तर पर स्कूल थे, जो सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा चलाए जाते थे, जिसमें पंचायतें, जिला बोर्ड और सरकार शामिल थे। धीरे-धीरे, पंचायत स्कूलों को जिला बोर्डों द्वारा अवशोषित कर लिया गया और अंततः, बाद वाले द्वारा प्रबंधित स्कूलों को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया।

हमें पंचायतों के अधीन शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों और जिला बोर्ड सेवा में शामिल होने पर उनकी सेवा की स्थिति से कोई सरोकार नहीं है, सिवाय इस बात के, कि एकीकरण में, जिला बोर्ड सेवा में प्रवेश की तारीख, पंचायत के तहत सेवा नहीं थी। वरिष्ठता की गणना के

प्रयोजनों के लिए प्रासंगिक माना जाता है। अगला संचालन यानी जिला बोर्ड के कर्मचारियों, शिक्षण और गैर-शिक्षण को सरकारी सेवा में शामिल किया जाना अब न्यायालय के विचाराधीन है। बुनियादी कानूनी विवादों को उजागर करने के लिए कुछ बुनियादी तथ्यों को ही दोहराने की जरूरत है।

1-4-70 से सभी जिला बोर्ड स्कूलों का अधिग्रहण कर लिया गया और, अनिवार्य रूप से, कर्मचारियों के विलय का मुद्दा सरकार के सामने आ गया।

16 मई 1970 के जी.ओ.नं.761 के जारी होने के समय, जिसने जिला बोर्ड सेवा से सरकारी सेवा में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के अवशोषण की व्यवस्था की, सरकार ने कर्मियों को एक अलग सेवा के रूप में समाहित रखने का निर्णय लिया जिसे शिक्षा विभाग ने तमिलनाडु शैक्षिक अधीनस्थ सेवा का नाम दिया। गैर-शिक्षण कर्मचारियों से संबंधित मंत्रालयिक सेवा को भी अलग रखा गया था। निःसंदेह, 1-4-70 के बाद खोले जाने वाले सभी स्कूल सरकारी स्कूल होने थे और इसलिए पूर्ववर्ती जिला बोर्ड स्कूलों और सरकारी स्कूलों के कर्मचारियों के बीच का द्वंद्व अब कायम नहीं रहा। दो अलग-अलग सेवाओं के इस अमिश्रणीय रखरखाव का सीधा परिणाम यह हुआ कि सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध पदोन्नति की संभावनाएं पूर्व जिला बोर्ड के कर्मचारियों के लिए सरकारी कर्मचारियों के रूप में उनके पुनर्जन्म पर खुली नहीं थीं। इसने, स्वाभाविक रूप से, दिल की जलन को जन्म दिया और लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसकी

अभिव्यक्ति, विधानमंडल में आंदोलन, प्रतिनिधित्व और हस्तक्षेप को जन्म दिया।

पूर्व जिला बोर्ड स्कूलों के कर्मचारियों की किस्मत में अगला विकास तब आया जब 17 अक्टूबर 1974 का जी.0.नंबर 1786 जारी किया गया। यहां सरकार ने 1-4-70 के बाद की स्थिति को दोहराया और दो सेवाओं के एकीकरण के सवाल पर नए सिरे से विचार किया, सरकारी स्कूलों के कर्मचारियों को 'ए' विंग कहा जाता है और पूर्व जिला बोर्ड स्कूलों के कर्मचारियों को 'बी' विंग कहा जाता है। सरकार के विचार में, 'ए' और 'बी' विंग का पूर्ण एकीकरण प्रशासनिक रूप से कठिन था और इसलिए उन्हें तमिलनाडु शिक्षा अधीनस्थ सेवा और तमिलनाडु शिक्षा सेवा के दो विंग के रूप में अलग रखा गया था। जिला बोर्ड स्कूलों से आने वाले नए छात्रों के लिए बेहतर संभावनाएं और पदोन्नति के रास्ते खोलने के लिए कुछ सुधारात्मक उपाय किए गए। संभवतः, यह आधी-अधूरी व्यवस्था शायद ही पर्याप्त तुष्टीकरण थी, और सरकार इस प्रश्न पर फिर से उत्तेजित हो गई। सामाजिक न्याय के दबाव ने विधायिका के सदनों सहित कई चैनलों के माध्यम से सरकार पर दबाव डाला, राज्य को एकीकरण के पूरे पैटर्न को बदलने और, एक सामान्य वरिष्ठता सूची में दोनों पक्षों को फिट करने के लिए राजी किया। सरकार ने इस प्रश्न पर इस प्रकार तर्क दिया:

"1-4-70 से 'बी' विंग कर्मियों को पूर्ण रूप से सरकारी

सेवक के रूप में कार्यभार संभालने के बाद से सरकार को

बार-बार यह बताया जा रहा था कि ऐसा नहीं होगा। जब दोनों विंग के लोग समान कार्य कर रहे हों तो 'ए' विंग में उनके समकक्षों को मिलने वाले लाभों से उन्हें हमेशा के लिए वंचित करना न्यायसंगत है और सरकार को कुछ तर्कसंगत आधार पर दोनों विंगों के विलय पर विचार करना चाहिए। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में भी कई माननीय सदस्य बार-बार सरकार से इस लंबे समय से लंबित मुद्दे पर शीघ्र और व्यावहारिक निर्णय लेने का आग्रह करते रहे हैं। मामले की गहनता से जांच करने के बाद विभिन्न कर्मियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए विवरण दोनों विंगों में श्रेणियां और उनके लिए पदोन्नति के अवसर, सरकार ने दोनों विंगों को एकीकृत करने के लिए एक फार्मूला अपनाने का प्रस्ताव दिया है और जहां तक संभव हो उनकी सेवा शर्तों को बराबर करने का प्रयास किया है। तमिलनाडु लोक सेवा आयोग ने इन प्रस्तावों पर अपनी सहमति दे दी है।

तदनुसार, सरकार अब जी.ओ. में आदेशों में आंशिक संशोधन का निर्देश देती है। जैसा ऊपर उल्लेख किया है कि 'ए' और 'बी' विंग के कर्मचारियों को नीचे बताई गई प्रक्रिया का पालन करते हुए तत्काल प्रभाव से एकीकृत किया जाए:"

(जोर दिया गया)

इसके बाद किस्मत की किस्मत तय करने वाले दो अहम फैसले हुए शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ स्तर पर दो विंग। रिट याचिकाओं में इन फैसलों को 'ए' विंग, यानी सरकारी स्कूलों के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों द्वारा मनमौजी, मनमाना और दर्दनाक बताया गया है। ये दो निर्णय संक्षेप में हैं, (1) प्रमोशन के मामले में दोनों विंगों के बीच अनुपात तय करना, और (2) सामान्य वरिष्ठता निर्धारित करने में सेवा की गणना के लिए सिद्धांत तय करना। इन रिट याचिकाओं में हमारा संबंध केवल माध्यमिक विद्यालयों के अराजपत्रित अधिकारियों से है। इनके संबंध में इस जी.ओ. संख्या 1968 में प्रमोशनल विचार हेतु अलग-अलग अनुपात तय किये गये हैं। दोनों समकक्ष समूहों में कुल संख्या का यथार्थवादी ध्यान रखते हुए, मंत्रालयिक कर्मचारियों और शिक्षण कर्मचारियों के लिए क्रमशः 5:3 और 3:2 का अनुपात निर्धारित किया गया था। क्वांडम जिला बोर्ड के सेवक और रिश्तेदार सरकारी स्कूल कर्मचारी। यह कोई अतार्किक मानदंड नहीं है जब दो स्रोतों से निकलने वाली दो धाराओं का सहसंयोजन होता है।

सेवा में न्यायशास्त्र एकीकरण एक जटिल प्रशासनिक समस्या है, जहां कई लोगों के साथ व्यापक न्याय करने में, कुछ को चोट लगने से इंकार नहीं किया जा सकता है। जोड़ों में कुछ खेल, यहां तक कि कुछ लड़खड़ाहट भी, बिना किसी झंझट वाली फोरेंसिक निगरानी के सरकार पर छोड़ दी जानी चाहिए, क्योंकि संविधान द्वारा प्रशासन को कार्यपालिका को

सौंपा गया है, न्यायालय को नहीं। प्रशासनिक जीवन सहित सारा जीवन, इसमें प्रयोग, परीक्षण और त्रुटि शामिल है, लेकिन मौलिक अधिकारों की अग्रणी श्रृंखला के भीतर, और, असंवैधानिक 'ज्यादतियों' के अभाव में, न्यायिक सुधार सही नहीं है। अनुच्छेद 32 के तहत यह न्यायालय संवैधानिक प्रहरी है, राष्ट्रीय लोकपाल नहीं। हमें एक लोकपाल की जरूरत है लेकिन अदालत ऐसा नहीं कर सकती।

यह कमजोर आलोचना कि अंतर-संयोजन और एकीकरण की प्रक्रिया में दोनों विंगों के बीच प्रमोशनल अनुपात किसी भी तर्कसंगत दिशानिर्देश द्वारा समर्थित नहीं है, व्यर्थ है। राज्य का मामला यह है कि जब दो स्रोत विलीन हो जाते हैं, पदोन्नति के लिए कोटा नियम का सहारा लेना असामान्य नहीं है, हालांकि आम पूल में आने के बाद सीमित वर्ग को छोड़कर आगे 'रंगभेद' पर रोक लगा दी जाएगी, जिससे हमारा यहां कोई लेना-देना नहीं है। बेशक, भले ही कोटा नियम हो एकीकृत प्रक्रिया में न्याय लाने के लिए एक प्रशासनिक उपकरण, अनुपात मनमाना नहीं हो सकता और न ही बाहरी कारकों पर आधारित हो सकता है। ऐसा कुछ भी न तो बताया गया है और न ही स्थापित किया गया है। चुनौती देने वाले पर जिम्मेदारी है और, यहां, अनुपात मध्यम रूप से दोनों पक्षों की संख्याओं से संबंधित है और हम देखते हैं कि कुछ भी 'निडर' नहीं हो रहा है, कुछ भी अजीब नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको यह पूछने के लिए अपनी आँखें रगड़ने पर मजबूर कर दे कि यह सरकार क्या अजीब

काम कर रही है? प्रतिवादियों के अधिवक्ता बताते हैं कि जब विभिन्न स्रोतों से समान समूहों को एक साथ लाया जाता है तो कोटा-रोटा अभियान क्षेत्र में परिचित व्यावहारिक उपकरण होते हैं। जिला बोर्ड के कर्मचारियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, यह अनुपात तर्कसंगत है। शायद, एक बेहतर सूत्र विकसित किया जा सकता है, लेकिन न्यायालय सरकार के लिए अपने विवेक को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती है, सिवाय यह देखने के कि अनुचित विकृति, दुर्भावनापूर्ण हेरफेर, असमर्थनीय मनमानेपन और इसी तरह की दुर्बलताएं एकीकरण के समीकरण को दूषित नहीं करती हैं। हम इस आधार पर आदेश को ध्वस्त करने से इनकार करते हैं। क्यूरियल थैरेप्यूटिक्स केवल असंवैधानिकता की विकृति को ठीक कर सकते हैं, न कि हर चोट को।

अधिक गंभीर आरोप यह है कि वरिष्ठता तय करने के लिए सेवा की अवधि ने 'ए' विंग यानी नियमित सरकारी कर्मचारियों पर स्पष्ट अन्याय किया है, जो मनमाने ढंग से पैदा हुए हैं और दुर्भावना से भरे हुए हैं। सामान्यताओं को बताना और फिर विशिष्टताओं की ओर बढ़ना उचित है। यहां हमें यह महसूस करना चाहिए कि सभी स्कूलों को राज्य द्वारा सीधे अधिग्रहित करने के बाद कर्मियों को मूल कपड़े में बुना जाना था। इस उद्देश्य के लिए कुछ प्रासंगिक सूत्र प्रस्तुत किए जाने थे ताकि समरूपीकरण एक समूह या दूसरे को अनुचित रूप से नुकसान न पहुँचाए। 1970 में सरकार ने एकीकृत करने का नहीं बल्कि अलग रखने का निर्णय लिया।

बाद में इस नीति को छोड़ दिया गया। यदि प्रशासनिक नीति संशोधित की जाती है तो हम अदालत के रूप में झगड़ा नहीं कर सकते। कल का ज्ञान आज की मूर्खता में बदल सकता है, जबकि पुराने समय का विज्ञान आज के अंधविश्वास में बदल सकता है, और इसके विपरीत भी। न ही हम केवल इसलिए दुर्भावनापूर्ण या गुप्त उद्देश्य का अनुमान लगा सकते हैं क्योंकि विधानसभा के भाषणों ने पुनर्विचार को प्रज्वलित किया है या, जैसा कि वकील ने संकेत दिया है, कि शिक्षा मंत्री की संवेदनशीलता उनके एक बार जिला बोर्ड शिक्षक होने के कारण है। लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं, ये दोनों ऐसी प्रक्रिया का हिस्सा हैं, जो न्यायाधीशों के लिए अभिशाप नहीं हैं और हम आदेश को रद्द नहीं कर सकते क्योंकि सरकार ने प्रश्नकाल में जवाब दिया है या एक संवेदनशील मंत्री के कहने पर निर्णय की दोबारा जांच की है।

केंद्रीय मुद्दा यह है कि क्या जिला बोर्ड के तहत लंबे समय तक सेवा में प्रत्यारोपित कर्मचारियों के पक्ष में नियुक्ति तर्कसंगत या मनमौजी, समानता-उन्मुख या अप्रिय है। विवादित G.O.No.1968, जो इन दो रिट याचिकाओं में हमले का केंद्र बिंदु है, पृष्ठभूमि के इतिहास, वर्तमान वास्तविकताओं और 1970 के बाद से लंबे समय से अवरुद्ध जिला बोर्ड स्रोतों के लिए खुले पदोन्नति के अवसरों को देने की आवश्यकता को निर्धारित करता है। इसमें लोक सेवा आयोग के परामर्श और सहमति का संदर्भ है जो आमतौर पर सेवा मामलों पर विशेषज्ञ निकाय है। इस जी.ओ. को प्रख्यापित करने के समय सरकार के पास 8 वर्षों का अनुभव उपलब्ध

है। यह तत्काल प्रभाव से 'ए' और 'बी' विंग के एकीकरण की नीति प्रस्तुत करता है और उस आधार की रूपरेखा तैयार करता है जिस पर ऐसा संलयन हासिल किया जाना है। एक राज्य-वार वरिष्ठता सूची तय की जाती है, एक ऐसी इच्छा जो एकीकरण को पूरा करने के लिए अपरिहार्य है।

शिक्षण पदों के संबंध में मौजूदा मूल रिक्तियों और पदोन्नति पदों को भरने के तरीके के संबंध में सरकारी निर्णय इस आक्षेपित जी.ओ. में दर्ज हैं। बेशक, गैर-शिक्षण पदों पर पदोन्नति द्वारा रिक्तियों को भरने के लिए भी इसी तरह के निर्णय लिए गए थे। शिक्षण पदों के संबंध में 5 के चक्र में 2:3 और गैर-शिक्षण पदों के संबंध में 8 के चक्र में 5:3, 'प्रत्यारोपण' के वर्तमान लॉट के मूल्यांकन के बाद सरकार का कोटा-रोटा निर्णय है, अतीत के छूटे अवसर और भविष्य में बढ़ती पदोन्नति।

एक निर्देश है कि उल्लिखित अनुपातों के अनुसार एक संयुक्त राज्य-व्यापी वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी और उसके बाद सभी पदोन्नतियाँ ऐसी संयुक्त सूचियों से की जाएंगी। 45 वर्ष की आयु पार कर चुके लोगों के संबंध में पदोन्नति के लिए आवश्यक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के संबंध में कुछ सुधारात्मक प्रावधान किए गए हैं। इस अंतिम अंग पर श्री स्वामीनाथन ने यह सुझाव देने के लिए भरोसा किया था कि दोनों सेवाओं के बीच कोई पूर्ण एकीकरण नहीं था। लेकिन इस कमजोर परिस्थिति से हमें ऐसे किसी निष्कर्ष का कोई निर्णायक संकेत नहीं मिलता। मामले की जड़ यह है कि आदेश में जो निहित है लेकिन स्पष्ट नहीं है, वह यह है कि

संयुक्त वरिष्ठता सूची के एकीकरण और संकलन की प्रक्रिया में सरकारी स्कूल के कर्मचारियों की तुलना में जिला बोर्ड के कर्मचारियों की सेवाओं को जिला बोर्ड सेवा में शामिल किया गया है। क्या यह किसी विवेकशील व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है या क्या जिला बोर्ड सेवा को सरकारी सेवा के समान समझना अपमानजनक है? यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर इन रिट याचिकाओं का निस्तारण करता है।

हमें विवरण में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समीकरण के क्षेत्र में, एक समग्र दृष्टिकोण, न कि एक सावधानीपूर्वक विच्छेदन, मायने रखता है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि सरकारी कर्मचारियों का शिक्षक या गैर-शिक्षक के रूप में चयन लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है, जिसका अर्थ है विशेषज्ञों द्वारा स्क्रीनिंग और प्रसंस्करण। दूसरी ओर, जिला बोर्ड के कर्मचारियों को अस्थायी अध्यक्ष की इच्छानुसार नियुक्त किया जाता है। स्पष्ट सुझाव यह है कि दोनों मामलों में पेशेवर उपकरण काफी हद तक अलग हैं। योग्यता के मामले में भी यह तर्क दिया जाता है कि स्कूलों में जिला बोर्ड के कर्मचारियों की तुलना में सरकारी कर्मचारियों की श्रेष्ठता है। रिट याचिकाओं में मतभेद की कुछ अन्य कम परिणामी परिस्थितियों पर भरोसा किया गया है। इसके विपरीत, उत्तरदाताओं की दलील यह है कि सेवा की गुणवत्ता में पर्याप्त समानता है और चयन प्रक्रिया में असमानता का अभाव है:

“सेवा आयोग की तरह, जिला बोर्ड ने भी उम्मीदवारों का चयन किया। जैसा कि पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है, 'ए' विंग के लोगों के लिए निर्धारित भाषा परीक्षण उनके लिए कोई अनोखी विशेषता नहीं है। इसलिए 'बी' विंग के लोगों के लिए निर्धारित परीक्षा और पाठ्यक्रम का वर्णन निश्चित रूप से दिखाएगा कि 'बी' विंग के लोगों को परीक्षाओं की कठिन प्रकृति का सामना करना पड़ा था। जहां तक शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता का सवाल है, इसमें कोई मतभेद नहीं है। ए-विंग में शिक्षक प्रशिक्षण की डिग्री के बिना भी उम्मीदवार को नियुक्त किया जा सकता है और बाद में वह बी.एड. में अर्हता प्राप्त कर सकता है। लेकिन जबकि बी विंग शिक्षकों के लिए, जिला बोर्ड अधिनियम के तहत बनाए गए नियम यह निर्धारित करते हैं कि माध्यमिक विद्यालय में स्कूल सहायक के पद के लिए, एक उम्मीदवार के पास मद्रास शैक्षिक नियम (नियुक्ति से संबंधित नियम) के तहत निर्धारित योग्यता होनी चाहिए स्थानीय निकायों द्वारा संचालित स्कूलों में शिक्षकों की संख्या)। मद्रास शैक्षिक नियमों के तहत किसी के पास बी.ए. की डिग्री होनी चाहिए। या बी.एससी., बी.टी. के साथ या बी.एड., जैसा कि मंत्रालयिक सेवा के मामले में होता है,

शिक्षकों को भी 2 साल की अवधि के लिए परीक्षा अवधि से गुजरना पड़ता है। 2 वर्ष की परीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी होने के बाद ही उन्हें नियमित किया गया। ऐसे नियमितीकरण के बाद ही उनकी वेतन वृद्धि स्वीकृत की जाती है। 'बी' विंग स्कूलों में एक प्राध्यापक या प्राध्यापिका को निम्नलिखित परीक्षण पास करने होंगे। यदि प्राध्यापक या प्राध्यापिका के रूप में पदोन्नत किया गया कोई उम्मीदवार इस विषय में असफल हो जाता है, तो उसे प्रत्यावर्तन का सामना करना पड़ेगा।”

जिन छात्रों को परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, ऐसे पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम और शिक्षण की प्रकृति स्कूलों के दो सेटों में लगभग समान होती है और शिक्षकों की योग्यताएं भी समान होती हैं। इस पृष्ठभूमि में, राज्य ने शायद इसके विपरीत तर्क को अस्वीकार्य मान लिया कि सेवा की गुणवत्ता, रोजगार के लिए योग्यता की प्रकृति और अन्य विशेषताएं वास्तव में समान थीं और परिणामस्वरूप जिला बोर्ड स्कूलों में सेवा और सरकारी स्कूलों में सेवा वरिष्ठता की गणना के प्रयोजनों के लिए समान वैध रूप से हो सकती है। इस अपूर्ण दुनिया में समीकरण में गणितीय परिशुद्धता एक व्यर्थ प्रयास है।

प्रतिवादियों के अधिवक्ता ने यह दिखाने के लिए हमारे सामने निर्णयों का हवाला दिया कि यह नवीनता का अभ्यास नहीं था और यहां तक कि

जब सरकार ने ऐसे कॉलेजों को अपने कब्जे में ले लिया है तो निजी कॉलेज के अनुभव को भी प्रासंगिक माना गया है। इसके विपरीत, याचिकाकर्ताओं के वकील ने हमारे सामने यह बात रखी कि जब पंचायत स्कूलों को जिला बोर्डों के शिक्षा विभाग में शामिल किया गया तो शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को पंचायत सेवा के लिए कोई श्रेय नहीं दिया गया और वरिष्ठता की गणना केवल जिला बोर्ड सेवा में प्रवेश की तारीख से की गई। जब जिला परिषद के शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को सरकारी सेवा में लाया जाता है तो एक अलग नियम क्यों अपनाया जाना चाहिए? यहां तक कि यह दिखाने के लिए 'मौलिक नियमों' का भी हवाला दिया गया कि आमतौर पर सरकारी सेवा में प्रवेश से पहले की सेवा को खारिज कर दिया जाता है, तो फिर नंबरों को खुश करने के लिए इस नियम का उल्लंघन क्यों? यह प्रश्न जी ओ संख्या 1968 को गलत ठहराने के लिए सरकार से पूछा गया है।

हमारे क्षेत्राधिकार की सीमा के बारे में जानते हुए भी हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि अदालत नीति में गलती करने के लिए ऐसी छोटी-छोटी बातों का विश्लेषण कर सकती है और सरकार के आदेश, यानी जी.ओ. नंबर 1968 को रद्द कर सकती है। तर्क के लिए, आइए मान लें कि पक्ष की ओर से पलटवार किया गया है, सेवा की लंबाई के संदर्भ में वरिष्ठता की गणना के मामले में सरकार अपना रुख बदल रही है। निश्चित रूप से, नीति स्थिर नहीं है, बल्कि गतिशील है और जब पंचायत संस्थानों को

जिला बोर्ड संस्थानों के साथ मिला दिया गया था, तो सरकार पर जो असर पड़ा था, उसे अनुभव या बदली हुई परिस्थितियों के मद्देनजर छोड़ दिया गया होगा। जिसे प्रशासनिक रूप से अव्यावहारिक माना जाता था, बाद में विचार और कार्यकर्ताओं के पुनर्विचार के बाद वह व्यवहार्य और निष्पक्ष साबित हो सकता है। न्यायालय किसी जी.ओ. या नीति को केवल इसलिए रद्द नहीं कर सकती क्योंकि उसमें भिन्नता या विरोधाभास है। जीवन कभी-कभी विरोधाभासी होता है और निरंतरता भी हमेशा एक गुण नहीं होती है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि क्या दुर्भावनाएँ बिगाड़ती हैं या अतार्किक और बाहरी कारक बिगाड़ते हैं। यह बनाए रखना असंभव है कि जिला बोर्ड के कर्मचारियों के रूप में सेवा की अवधि एक मानदंड के रूप में तर्कहीन है। आइए तर्क के लिए मान लें कि जिला बोर्डों द्वारा चयन का तरीका लोक सेवा आयोग जितना अच्छा नहीं है। फिर भी सरकार की इस स्थिति को खारिज करना मुश्किल है कि ज्यादातर समान योग्यता वाले, समान कार्य करने वाले और समान परीक्षाओं के लिए समान छात्रों को प्रशिक्षित करने वाले शिक्षकों को मनमानी के दोषी के रूप में निंदा किए बिना व्यावहारिक दृष्टिकोण से बराबर नहीं किया जा सकता है।

श्री गोविंद स्वामीनाथन ने इस बात पर ज़ोर दिया कि कुछ मामलों में तो 'ए' विंग के कुछ सौ सदस्यों को भी 'बी' विंग में उनसे कहीं कनिष्ठ किसी व्यक्ति ने पास कर दिया है। एक बार जब सिद्धांत तर्कसंगत पाया जाता है तो तथ्य यह है कि कठिनाई के कुछ अजीब उदाहरण दोनों तरफ

उत्पन्न हो सकते हैं, आदेश या नीति को अमान्य करने का आधार नहीं हो सकता है। प्रत्येक कारण एक शहीद का दावा करता है और कल के वरिष्ठों को आज कनिष्ठ बनते देखकर हम चाहे कितने भी दुखी क्यों न हों, यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां, मनमानी और तर्कहीनता के अभाव में, न्यायालय को एक हाथ से चलने वाली नीति अपनानी पड़ती है।

'बी' विंग के सदस्यों की शिकायत है कि 1970 के बाद इन सभी वर्षों में सेवा की अवधि के कारण उन्हें जो मिलना चाहिए था, उससे वंचित किए जाने से उन्हें वास्तव में बहुत नुकसान हुआ है। किताब दूसरे चरण में है, वे विलाप करते हैं। संभवतः, अतीत का अन्याय, जब अचानक वर्तमान की समता से ठीक हो जाता है, तो एक विकृत स्थिति पैदा कर देता है और यथास्थिति के लाभार्थी अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ मदद की गुहार लगाते हैं। कानून, सामाजिक न्याय के एक साधन के रूप में, इतिहास के पापों को बेअसर करने के लिए एक लंबा प्रयास करता है। चाहे जो भी हो, न्यायिक शक्ति वहां जल्दबाजी नहीं कर सकती जहां प्रशासनिक अधिकारी भी कदम रखने से डरते हैं।

हम याचिकाकर्ताओं की शिकायत में बल देखते हैं और महसूस करते हैं कि एक वैकल्पिक नीति भी बनाई जा सकती है। यह राज्य का मामला है, न्यायालय का नहीं।

हम मानते हैं कि विवादित जी.ओ. को अनुच्छेद 14 और 16 के उल्लंघन के रूप में अवैध नहीं किया जा सकता है, और इसलिए, याचिकाओं को खारिज करते हैं। पक्षकार अपना-अपना खर्च वहन करेंगे।

एनवीके.

याचिकाएं खारिज की गईं।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक विनायक कुमार जोशी, अधिवक्ता द्वारा किया गया है ।

अस्वीकरण- इस निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।
